विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): योजना आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए वास्तविक कार्यक्रम और वित्तीय परिव्ययों के संबंध में निर्णय वर्ष दर वर्ष आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और संबंधित राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करके संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों के प्रस्तावों, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्डों की तत्परता तथा राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति आदि के आधार पर लिए जाते हैं। किसी भी गांव को विद्युतीकृत उस दशा में समझ लिया जाएगा यदि बिजली का किसी भी प्रयोजन से गांव की राजस्व सीमा के भीतर उपयोग किया जाता है।

मध्य प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

4380. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के गांवों के विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और क्या वांछित परिणाम प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य के सभी गांव कब तक विद्युतीकरण हो जायेंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) योजना आयोग ने वर्ष दर वर्ष आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-93 से 1996-97) के दौरान 1970 गांवों के विद्युतीकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसकी अपेक्षा में मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने मार्च, 1997 (अनंतिम) तक 3278 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की सूचना दी है।

(ग) मध्य प्रदेश में शेष गैर-विद्युतीकृत गांवों को नौवीं और उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युतीकृत किया जाएगा बशर्ते निधियां और अन्य आवश्यक निवेश उपलब्ध हों।

Generation Cost and Average Tariff of Electricity

4381. DR. B.B. DUTTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what was the generation cost of per KW of electricity during 1995-96;

(b) what has been the average tariff, per KW, for agriculture sector, industrial sector and domestic sector during the above period;

(c) whether the low tariff for agriculture is one of the reasons for losses of SEBs; and

(d) if so, whether Government propose to increase tariff rates for agriculture or gross subsidisation of power supply for agriculture sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) The all India average cost of supply of electricity during 1995-96 was 179 paise/kwh.

(b) The all India average tariff of electricity from different category of consumers during 1995-96 were as under:—

Agriculture Sector	47 Paise/kwh
Domestic Sector	169 Paise/kwh
Industrial Sector	234 Paise/kwh

(c) Yes, Sir.

(d) The Common Minimum National Action Plan for Power (CMNAPP) finalised in the Chief Ministers' Conference on Power held on 16th October, 1996 and 3rd December, 1996, inter alia, aims at establishment of State Electricity Regulatory Comissions (SERC) in each State/UT for determination of tariffs; no sector paying less than 50% of the average cost of supply, agriculture tariff not being less than 50 paise per kwh to be brought to 50% of the average cost in not more than 3 years; recommendations of SERCs being mandatory and for any deviations from tariff recommended by it, the State Governments/UTs to provide for the financial implications of such deviations explicitly in the State/UT budget and a package of incentives and disincentives to encourage and facilitate the implementation of tariff rationalisation by the States.